मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

महारानी उषादेवी

(सिविल अपील संख्या 557-558/2012),

15 जुलाई 2015

[रंजन गोगोई और एन.वी. रमण, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 363 - प्रयोज्यता - शीर्षक और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए मुकदमा - होल्कर के महाराजा के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा - यह दावा करते हुए कि विचाराधीन संपत्ति जिसका प्रबंधन होल्कर राज्य के घरेलू विभाग द्वारा महाराजा की विशिष्ट और व्यक्तिगत संपत्ति का किया जाता था, न कि अपीलकर्ता-राज्य की संपत्ति - विकल्प में भूमि के 'भूमिस्वामी' होने की घोषणा की मांग की जा रही है। भूमि राजस्व संहिता की धारा 158(2) - मुकदमे की रखरखाव – अभिनिर्धारित : वादी का अधिकार उस अनुबंध से प्राप्त होता है जिसके तहत होलकर के महाराजा और अन्य रियासतें भारत के प्रभुत्व के साथ विलय के लिए सहमत हुईं - इसलिए, वादी द्वारा की गई राहत की मांग अनुच्छेद 363 के दायरे में आती है और इसलिए यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है - चूंकि वादी का 'भूमिस्वामी' के रूप में दावा अनुबंध के माध्यम से है जो विवादित है और इन विवादों को निपटाने की राहत अनुच्छेद 363 के तहत वर्जित है, कोई भी प्रसंविदा से स्वतंत्र, 'भूमिस्वामी' होने का दावा नहीं कर सकता - मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 – धारा 158(2)

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : 1.1 अनुबंध के अनुच्छेद 12(2) के अनुसार (जिसके तहत होल्कर के महाराजा अन्य रियासतों के साथ भारत के डोमिनियन में विलय के लिए सहमत हुए), होल्कर के महाराजा ने विभिन्न शीर्षकों के तहत संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया है। वाद की सपंत्तियां जो वादी के कब्जे में है, संपत्तियो की पूरी सूची में उनका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वादी को संपत्तियों की सूची के खंड 14 से संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त होता है जो घरेलू विभाग के नियंत्रण में सभी संपत्तियों के बारे में बताता है। वाचा वादी के लिए शीर्षक का स्रोत है। हर तरह से वादी का अधिकार अनुबंध से आता है जिसके आधार पर वादी इन संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा करता है, जो उसके अनुसार शासक की निजी संपत्ति घोषित की जाती हैं। किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वादी का अधिकार पहले से मौजूद अधिकार है। [पैरा 28 और 29] [756-सी-डी, एफ; 757-ए-सी]

1.2 संविधान के अनुच्छेद 363 का मात्र अवलोकन और मुकदमे में वादी द्वारा स्पष्ट शब्दों में मांगी गई राहत अनुच्छेद 363 में निहित प्रतिबंध को आकर्षित करती है। प्रसंविदा राज्य का एक अधिनियम है और इसकी शर्तों से उत्पन्न कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में विषय वस्तु नहीं बन सकता है, और किसी भी बाद के चरण में संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में कोई निहित मान्यता नहीं दी जा सकती है जब परिभाषित अवधि से पहले ही अनुच्छेद 12 के खंड 3 के संदर्भ में मुद्दा उठाने का अवसर दिया गया हो; सबसे बढ़कर, संपत्तियों को अनुबंध में जगह नहीं मिलती है। वर्तमान मामले में, वादी की ओर से अनुबंध की व्याख्या कि सभी संपत्तियां जो घरेलू विभाग की हिरासत में हैं, शासक की निजी संपत्ति हैं, एक निहित मान्यता अस्वीकार्य है। इसलिए, मुकदमे में राहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के दायरे में आती है और मुकदमा चलने योग्य नहीं है। [पैरा 30 और 34] [757-डी; 759-ई-जी, एच; 760-ए]

द्रौपदी देवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2004 (4) पूरक एससीआर 223: (2004) 11 एससीसी 425; माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ एआईआर 1971 SC 53: 1979 (2) SCR 62; करण सिंह (डॉ.) बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य 2004 (1) पूरक एससीआर 43: (2004) 5 एससीसी 698 - पर भरोसा व्यक्त किया ।

2. भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(2) के अनुसार, एक शासक के पास भूमि होनी चाहिए या वह एक प्रसंविदा के आधार पर ऐसे शासक के रूप में भूमि रखने का हकदार होना चाहिए या उसके द्वारा किया गया समझौता। वादी/प्रतिवादी प्रसंविदा से स्वतंत्र भूमिस्वामी का दर्जा नहीं मांग सकता क्योंकि धारा 158(2) के तहत अधिकार प्रसंविदा से ही उत्पन्न होते हैं। भूमि को धारण करने का स्रोत एक अनुबंध के आधार पर उत्पन्न होता है। जब अनुबंध के माध्यम से दावा किया गया अधिकार विवादित है और संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत इन विवादों को निपटाने की राहत वर्जित है, तो कोई भी स्वतंत्र रूप से मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 158(2) के तहत "भूमिस्वामी' होने का दावा नहीं कर सकता है। वाचा का। [पैरा 40] [762-एच; 763-ए-सी]

3. वादी द्वारा मांगे गए सभी अधिकार केवल प्रसंविदा से प्राप्त अधिकार हैं। जैसा कि अनुबंध के खंड 12(1) के तहत प्रदान किया गया है, दिनांक 29-9-1962 के पत्र द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी/वादी ने अनुबंध के माध्यम से शीर्षक का दावा किया है, न कि ऐसे किसी किरायेदारी अधिकार के द्वारा। इसलिए, प्रतिवादी वादी वाद अनुसूची संपत्तियों पर किरायेदारी के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है और ऐसी याचिका गलत है और उसे ऐसी याचिका उठाने से रोका गया है। [पैरा 39] [762-सी-डी]

4. यह मानते हुए भी कि विचाराधीन संपत्तियां घरेलू विभाग के नियंत्रण में हैं, फिर भी वादी इस कारण से सफल नहीं हो सकता क्योंकि सुसज्जित संपत्तियों की सूची में होल्कर के महाराजा इन संपत्तियों का विशेष रूप से उल्लेख करने में विफल रहे हैं, और स्थापित कानून के अनुसार अनुबंध की व्याख्या की अनुमति नहीं है। [पैरा 38] [768-ए-बी]

5. इन सभी कारकों के बावजूद कि महाराजा और वादी के पास लगातार संपत्ति का कब्ज़ा था और उन्होंने संपत्तियों के लिए ताउज़ी को भुगतान किया था, वादी का कब्ज़ा कितना भी लंबा क्यों न हो और करों का भुगतान करने से उसे इन संपत्तियों के स्वामित्व की घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा एक प्रसंविदा का हिस्सा हैं और प्रसंविदा की व्याख्या की मांग करते हैं। इसके अलावा, वादी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासकीय सामान्य, प्रशासनिक विभाग, भोपाल को दिनांक 1 अक्टूबर 1962 को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने सूट की अनुसूचित संपत्तियों को महाराजा होल्कर द्वारा घोषित निजी संपत्तियों के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कार्रवाई का पूरा कारण और मुकदमे में मांगी गई राहतें अनुबंध और अनुबंध से प्राप्त अधिकारों पर आधारित हैं। [पैरा 37] [761-डी-जी]

6. यह स्थापित कानून है कि पार्टियां अपनी दलीलों से शासित होती हैं और जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है जो साबित करने की दलील देता है और इसके अलावा वादी को अपने मामले की ताकत के आधार पर सफल होना होता है और वह प्रतिवादी के मामले की कमजोरी पर निर्भर नहीं रह सकता है। कई आरोप लगाने के बाद भी राज्य यह दिखाने के लिए किसी भी दस्तावेज़ को चिह्नित करने में विफल रहा है कि संपत्तियों को वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और वर्ष 1951 में पुनर्हस्तांतरण बिना किसी कानूनी अधिकार के किया गया था। हालाँकि राज्य ने इस

न्यायालय के समक्ष कुछ दस्तावेज़ दाखिल किए हैं, लेकिन चूँकि वे साक्ष्य का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन पर गौर नहीं किया जा सकता है। [पैरा 35] [760-ई-जी]

<u>प्रकरण कानून संदर्भ</u>

2004 (4) पूरक एससीआर 223	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 30
1979 (2) एससीआर 62	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 32
2004 (1) पूरक एससीआर 43	भरोसा व्यक्त किया	पैरा 33

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 557-558/2012

समीक्षा याचिका संख्या 396/2010 और प्रथम अपील संख्या 421/2001 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 13.08.2010 और 11.02.2011 से।

टी. आर. अंध्यारुजिना, सी.डी. सिंह, सनी चौधरी, शोमिक; अपीलकर्ता की ओर से।

सी. ए. सुंदरम, पुनीत जैन, मनोज श्रीमाल, मनु माहेश्वरी, अभिनव गुप्ता, जेड अनायत, रोहिणी मूसा, प्रतिभा जैन; प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एन. वी. रम्मना, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। 1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के दिनांक 13.08.2010 और 11.02.2011 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री के खिलाफ प्रथम अपील संख्या 421 /2001 और समीक्षा याचिका संख्या 396/2010 में दायर की गई हैं। जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता/राज्य के पक्ष में पारित विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द करते हुए, प्रतिवादी के पक्ष में स्वामित्व की

घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया और अपीलकर्ता/राज्य द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया।

2. इन अपीलों के लिए तथ्य, संक्षेप में, यह है कि प्रतिवादी/वादी, जो कि होलकर राज्य के पूर्व शासक, महाराजा यशवंत राव होलकर की बेटी और कथित तौर पर एकमात्र उत्तराधिकारी थी, ने राहत की मांग करते हुए 7 सितंबर 1964 को वर्तमान मुकदमा वाद अनुसूची संपत्तियों के संबंध में शीर्षक और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा, यानी, बिजासन, आशापुरा, बेरचा, मोहना और गाजीहाटा के नाम से जाने जाने वाले बीर, दायर किया था और वैकल्पिक रूप से घोषणा की मांग की गई कि वादी सरकारी पट्टेदार या वाद अनुसूची संपत्तियो का भूमिस्वामी है। वादी का यह विशिष्ट मामला है कि ये बीर प्रारंभ में होलकर राज्य के घरेलू विभाग के नियंत्रण में थे। होलकर राज्य के अस्तित्व के दौरान किसी समय इन चार बीरों की घास को काटने और इकट्ठा करने का काम इंदौर के मिलिट्री ग्रास फार्म को इस निर्देश के साथ सौंपा गया था कि उन्हें घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक घास की मात्रा की आपूर्ति की जाएगी।

3. महाराजा यशवन्त राव होल्कर के जीवनकाल में वे तौजी कर निर्धारण/राजस्व शुल्क होल्कर राज्य के खजाने में जमा करते रहे थे। 31-08-1945 को, प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए, घास की कटाई के लिए, इन बिरों को होलकर राज्य के सेना विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। 22-01-1951 को फिर से, इन बीरों को महाराजा को हस्तांतरित कर दिया गया और उस तिथि से, मुकदमा दायर होने तक ये बीर वादी के परिवार के निरंतर कब्जे और आनंद में हैं। वर्ष 1948 में, होलकर राज्य को अन्य रियासतों के साथ 16 जून, 1948 की संधि के अनुसार भारत के डोमिनियन में विलय कर दिया गया था, जिसे बाद में वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के एक हिस्से के रूप में पुनर्गठित किया गया था। 7 मई, 1949 को महाराजा यशवन्त

राव होल्कर और भारत सरकार, राज्य मंत्रालय के बीच हुए अनुबंध के अनुच्छेद XII के अनुसार, घरेलू विभाग द्वारा प्रबंधित की जा रही भूमि, वादी के पिता की विशेष और व्यक्तिगत संपत्ति बन गई। चूंकि संपत्ति महाराजा की है, इसलिए सरकार ने भी उक्त भूमि के लिए राजस्व की मांग की, जिसे वादी के पिता के साथ-साथ वादी द्वारा भी विधिवत जमा किया गया था।

4. वादी का यह भी मामला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने 2 मई, 1964 को कुछ आदेश पारित किए थे, जिसके आधार पर, कलेक्टर, इंदौर ने 16 मई, 1964 को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें वादी को जमीन का कब्जा सौंपने की आवश्यकता थी। विचाराधीन भूमि इस आधार पर कि राज्य सरकार ने सूट अनुसूची संपत्ति को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया है। वादी के अनुसार, वह इन भूमियो या तो मालिक के रूप में या सरकारी पट्टेदार के रूप में इन्हें रखती है, और सरकार के पास ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तब वादी ने विवाद का निपटारा करने के लिए मध्य भारत भू-राजस्व संहिता की धारा 57 के तहत उप-विभागीय मजिस्ट्रेट का रुख किया, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, वादी घोषणा और निषेधाज्ञा से राहत की मांग करते हुए वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य था।

5. अपीलकर्ता/प्रतिवादी/राज्य ने वाद की भूमि पर वादी के स्वामित्व पर विवाद करते हुए लिखित बयान दाखिल करके मुकदमे का विरोध किया। प्रतिवादी के अनुसार, महाराजा यशवन्त राव होलकर कभी भी सूट अनुसूचित संपत्ति के मालिक नहीं थे। इसलिए, वादी के संपत्ति पर उत्तराधिकार का सवाल ही नहीं उठता। बीर होलकर राज्य के वन विभाग की संपत्ति थे। 21 अगस्त, 1926 को होल्कर राज्य के मंत्रिमंडल ने बिजासन बीर को घरेलू विभाग में स्थानांतरित कर दिया, और बाद में शेष बीर को भी

मूल्यांकन के निपटारे पर स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इन बीरों को वर्ष 1930 में वन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1943 में फिर से इन्हें घरेलू विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रतिवादी का मामला यह है कि वर्ष 1945 में, सभी बीर होलकर राज्य के सेना विभाग के पास थे, जिसे घरेलू विभाग को घास की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। भारत के डोमिनियन के साथ होलकर राज्य के विलय के समय, ये बीर सेना विभाग के साथ थे और इसलिए निजी संपत्तियों की सूची के आइटम नंबर 14 के अनुसार और इन सभी आधारों के अलावा, इसे महाराजा की निजी संपत्ति नहीं माना जा सकता है। आग्रह किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत रोक के मद्देनजर यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। उपरोक्त दलीलों के आधार पर, प्रतिवादी ने मुकदमे को खारिज करने की मांग की।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1979 में, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में धारा 158(2) को शामिल किया गया था। उक्त प्रावधान के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बनने वाले एक भारतीय राज्य के शासक, जो अधिनियम के लागू होने के समय भूमि धारण कर रहा था अथवा अनुबंध के आधार पर भूमि धारण करने का हकदार था, संहिता के लागू होने की तारीख से, ऐसी भूमि की भूमिस्वामी बन जाएगी। वादी भी उक्त प्रावधान के तहत आश्रय चाहता है।

7. वादी की ओर से, कई बड़े दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रदर्शन के रूप में चिन्हित किया गया था, जबकि प्रतिवादियों की ओर से, केवल दो दस्तावेजों को चिह्नित किया गया था। विचारण न्यायालय ने लगभग 20 मुद्दे तय किए हैं, दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों की सराहना की है और अंततः 9 मार्च, 1992 के फैसले और डिक्री द्वारा, तीन बीर और गंजिहाटा के संबंध में वादी द्वारा दायर मुकदमे को आंशिक रूप से अनुमति दी है, और परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा भी दी गई। इसके खिलाफ, राज्य ने

प्रथम अपील संख्या 148/1992 को प्राथमिकता दी है, और वादी ने 119 /92 की पहली अपील दायर की है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24-03-2000 द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है और मुकदमे के लिए अन्य चार अतिरिक्त मुद्दे तय करके नए निर्णय के लिए मामला रिमांड पर ले लिया है। रिमांड के समय, अपीलीय अदालत द्वारा यह भी देखा गया कि मामले पर दोबारा फैसला करते समय, विचारण न्यायालय कोई और सबूत दर्ज नहीं करेगा और न ही पक्षों को दलीलों में कोई संशोधन करने की अनुमति देगा।

8. विचारण न्यायालय ने रिमांड के बाद 24 मुद्दे तय किए, और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों की सराहना करने के बाद, 17-08-2001 के निर्णय और डिक्री द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया। यह विचारण न्यायालय की विशिष्ट खोज है कि वाद अनुसूची भूमि का हस्तांतरण वर्ष 1951 में घरेलू विभाग के लिए कोई अधिकार नहीं है और इसलिए बुरा है; नियम के अनुसार तौज़ी को 1951 से भुगतान किया गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तौज़ी को 1951 से पहले की अवधि के लिए भुगतान किया गया था; वादी और उसके पिता द्वारा सरकार के साथ दर्ज किए गए पत्राचार से पता चला कि वाद की अनुसूचित संपत्ति प्रदर्श पी.78 के मद नंबर 14 में शामिल नहीं थी; साधारण किरायेदार, सरकारी पट्टेदार या मालिक के रूप में वाद अनुसूची संपत्तियों का कब्जा नहीं था; कि वाद अनुसूची भूमि राज्य के द्वारा वन विभाग को आवंटित नहीं की गई थी; और अंततः, विचारण न्यायालय ने माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 में निहित रोक के मद्देनजर, मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

9. विचारण न्यायालय के उक्त फैसले और डिक्री के खिलाफ, वादी ने प्रथम अपील संख्या 421 /2001 को प्राथमिकता दी। विद्वान न्यायाधीश ने विचार के लिए निम्नलिखित दो मुद्दों का निपटारा किया:

ए. क्या 16 जून, 1948 को होल्कर राज्य के मध्य भारत राज्य में विलय के समय प्रश्नगत संपत्ति को महाराजा यशवंत राव होल्कर की निजी संपत्ति माना जा सकता है?

बी. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 में निहित रोक विचाराधीन विवाद पर लागू होती है ताकि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को वर्जित माना जा सके?

10. विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 13 अगस्त, 2010 के निर्णय डिक्री द्वारा, विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मुकदमे का फैसला सुनाया, इस आशय के निष्कर्ष दर्ज करके कि विलय की तारीख पर, वाद अनुसूची संपत्तियां घरेलू विभाग की थीं और कि भूमि एक विशिष्ट समय और विशिष्ट उद्देश्य के लिए हस्तांतरित की गई थी; 3 मई, 1951 को भूमि का पुन: हस्तांतरण पी 78 को प्रदर्शित करने के लिए अनुबंध की मद संख्या 20 के अनुरूप था, जो भूमि सौंपने के लिए मध्य भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का प्रावधान करता है; मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 158(2) के आधार पर, वादी के पिता भूमि धारण करके भूमिस्वामी बन गए, और इस तरह, अधिनियम की धारा 158(2) के तहत लाभ के हकदार थे; वे शासक जो भारत के डोमिनियन के साथ अपने राज्यों के एकीकरण से पहले संप्रभु थे और एकीकरण के बाद भारत के नागरिक बन गए हैं, और भारत के नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है; 1 जुलाई, 1949 के बाद राज्य भी विवाद नहीं उठा सकता और केवल कार्यकारी आदेश को तब तक कायम नहीं रखा जा सकता जब तक कि इसे कानून के कुछ प्राधिकारियों द्वारा

समर्थित नहीं किया जाता है, मुकदमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत वर्जित नहीं है क्योंकि यह वादी के पहले से मौजूद अधिकार पर आधारित है और अनुबंध से बहने वाले अधिकारों पर आधारित नहीं है।

11. विद्वान न्यायाधीश ने माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ, एआईआर 1971 एससी 53, सवाई तेई सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1979 एससी 126, द्रौपदी देवी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2004) 11 एससीसी 425, डॉ. करण सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर और अन्य, (2004) 5 एससीसी 698 में इस न्यायालय के फैसले पर विचार किया और उन्हें यह देखते हुए अलग किया कि उन मामलों में, निजी संपत्तियों के रूप में संपत्तियों की कोई घोषणा नहीं की गई थी, और वह राज्य सरकार द्वारा पारित कार्यकारी आदेश कानून के अनुरूप नहीं थे और इस तरह की व्याख्या से कानून का शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए, न्यायालय के समक्ष लाए गए विवाद को इस आधार पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 363 मुकदमे को रोकता है। विद्वान न्यायाधीश ने सांवल तेज सिंह के मामले को यह कहते हुए अलग कर दिया कि उक्त मामले में, संपत्तियों को निजी संपत्तियों के रूप में मान्यता देने की वादी की याचिका को सरकार ने खारिज कर दिया था, लेकिन वर्तमान मामले में, शासक की निजी संपत्तियों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, और इसलिए, उक्त निर्णय का अनुपात मौजूदा मामले पर लागू नहीं था; न्यायाधीश ने द्रौपदी देवी के मामले को प्रतिष्ठित करते हुए कहा कि उस मामले में विवादित संपत्ति को किसी भी स्तर पर शासक की निजी संपत्ति घोषित नहीं किया गया है, और इसलिए, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था, क्योंकि मौजूदा मामले में, संपत्तियों को पहले से ही निजी संपत्तियों के रूप में घोषित किया गया है।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के कारण होल्कर के महाराजा और सरकार के बीच दिनांक 16.6.1948 की संविदा से उत्पन्न विवाद में उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र था। विद्वान वकील का कहना है कि वर्तमान मुकदमा अनुच्छेद 363 के दो अंगों के अंतर्गत आता है क्योंकि वर्तमान विवाद स्पष्ट रूप से अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न होता है। इसलिए, विचारण न्यायलय ने प्रतिवादी के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों और कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करके एक बड़ी गलती की। संपत्तियों की सूची के आइटम नंबर 14 के संदर्भ में संबंधित संपत्तियों को दिवंगत महाराजा की निजी संपत्ति घोषित करने का दावा, अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न एक विवाद था, और इसका अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान की धारा 363 में कहा गया है कि ऐसे दावों पर निर्णय देने के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी गई है।

13. द्रौपदी देवी (उपरोक्त) से समर्थन प्राप्त करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह विवाद कि क्या किसी विशेष संपत्ति को शासक की निजी संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी या नहीं, स्वयं अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न विवाद था, संविधान के अनुच्छेद 363 के कारण न्यायालयो के अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। मुकदमे की उत्पत्ति भारत सरकार के 3 अक्टूबर, 1963 के पत्र से होती है, जिसमें मद संख्या 14 के तहत विवादित बीरों को शासक की निजी संपत्तियों की सूची में शामिल करने के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, वादी का दावा यह स्पष्ट रूप से अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न होने वाला विवाद है और ऐसे विवादों पर निर्णय देने के लिए न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 363 के आधार पर स्पष्ट रूप से वर्जित है।

14. आगे यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखने में विफल रहा है और यह घोषित करने में गंभीर गलती की है कि विचाराधीन बीर प्रतिवादीगण/वादी के पिता स्वर्गीय महाराजा की निजी संपत्ति हैं। ये संपत्तियाँ दिवंगत महाराजा की निजी संपत्तियों की सूची में कहीं भी शामिल नहीं थीं, न ही बीरों को कभी भी राज्य द्वारा निजी संपत्तियों के रूप में स्वीकार किया गया था और इसलिए प्रतिवादी कभी भी इन बीरों के स्वामित्व में सफल नहीं हुआ था। "संविदा की व्याख्या" की आड़ में, प्रतिवादी इन बीरों पर अधिकार हड़पना चाहता है जो शुद्ध सरकारी संपत्ति हैं। केवल इन बीरों पर स्वामित्व का दावा करने के एक गुप्त उद्देश्य से, जैसे कि वे स्वर्गीय महाराजा की निजी संपत्ति थीं, प्रतिवादी ने विवादित भूमि को शासक की निजी संपत्तियों की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को 29 दिसंबर, 1962 को पत्र लिखा था। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और विलय के बाद, मध्य भारत सेना के केंद्र का भारत सरकार में विलय कर दिया गया था और भारत सरकार के रक्षा विभाग ने इन भूमियों का प्रभार ले लिया था, तब ये बीर आर्मी ग्रास फार्म के कब्जे में थे। जब भारत सरकार ने 1955 में कुछ आर्मी ग्रास फार्मों को बंद करने का निर्णय लिया, तो विवादित बीड़ियों को राज्यों के संबंधित विभागों को वापस लौटाने का आदेश दिया गया। इसलिए, विचाराधीन भूमि का सही ढंग से और जानबूझकर शासक की निजी संपत्तियों की सूची में उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि वे तब भारत सरकार के अधीन थे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत कलेक्टर, इंदौर को दिनांक 12.6.1964 को प्रतिवादी का कानूनी नोटिस स्पष्ट रूप से उसकी स्वीकारोक्ति को बताता है कि संघीय वित्तीय एकीकरण के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 6.10.1955 को एक आदेश दिया गया था जिसके तहत संपत्तियों में प्रश्न को मध्यभारत शासन में निहित करने का आदेश दिया गया। भारत सरकार ने अपने दिनांक 3 अक्टूबर, 1963 के पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से कहा कि होलकर आर्मी

ग्रास फार्म द्वारा इन विवादित भूमियों के कब्जे का घरेलू विभाग को पुनः हस्तांतरण अनधिकृत था और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(2) के तहत लाभ के लिए प्रतिवादी को अर्हता देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी मनमाना और पूरी तरह से गलत है क्योंकि धारा 158(2) संहिता के अनुसार, संविधान के प्रारंभ से पहले उसके द्वारा दर्ज की गई संविदा या समझौते के आधार पर भूमि रखने वाला शासक ही भूमिस्वामी होगा। वर्तमान मामले में जहां अनुबंध के माध्यम से अधिकारों की प्रयोज्यता स्वयं विवाद में है, अनुबंध के आधार पर कोई भूमिस्वामी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। यदि वादी ने इन बीरों के लिए कोई राजस्व का भुगतान किया था, तो यह केवल तथ्य की अनदेखी में किया गया था और उस आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि ये भूमि कभी भी वादी को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है। इसके अलावा, दो बीर अर्थात् बिजासन और बेरछा आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा हैं और उन पर प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

16. अपने तर्कों को सारांशित करते हुए, राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंततः प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों की गलत सराहना करते हुए, अनुच्छेद 363 में निहित संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, और इस पर गौर भी नहीं किया। उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समीक्षा के आधार पर, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का हनन हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII के साथ पढ़ी गई धारा 114 के संदर्भ में नए दस्तावेज़ की खोज के आधार पर निर्णय की समीक्षा की भी अनुमति है। इस प्रकार

उच्च न्यायालय का निर्णय संविधान के दायरे से बाहर है और इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णयों को रद्द किया जाना आवश्यक है।

17. प्रतिवादी-वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलकर्ता द्वारा कुछ दस्तावेजों को दाखिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई, जिन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रदर्शित नहीं किया गया था और प्रस्तुत किया गया था कि जब अपीलकर्ता ने पहली बार इन दस्तावेजों को समीक्षा याचिका के साथ रिकॉर्ड पर रखने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। मामले को विचारण न्यायालय में भेजते समय भी, उच्च न्यायालय ने 24 मार्च, 2000 के अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि "मामले पर दोबारा फैसला करते समय, ट्रायल कोर्ट कोई और सबूत दर्ज नहीं करेगा और न ही पक्षों को इसमें कोई संशोधन करने की अनुमति देगा।" अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के इस निर्देश को चुनौती नहीं दी और वास्तव में, अपीलकर्ता ने इस निर्देश का पालन करते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई किए जाने पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई अतिरिक्त सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया। इतने वर्षों की मुकदमेबाजी के बाद, इस न्यायालय के समक्ष पहली बार कुछ दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

18. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत रोक वर्तमान मुकदमे पर लागू नहीं होती है क्योंकि प्रतिवादी न तो किसी सम्मिलन की मांग कर रहा है और न ही किसी ऐसी चीज़ की मान्यता चाहता है जो पहले से ही वाचा में मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसा कि विद्वान वकील ने तर्क दिया, विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का अधिकार, अनुबंध से उत्पन्न होने वाला अधिकार नहीं है, बल्कि यह पहले से मौजूद अधिकार है क्योंकि विवाद में संपत्ति हमेशा तत्कालीन शासक घरेलू विभाग की थी। प्रतिवादी-वादी न तो अनुबंध पर विवाद कर

रहा है और न ही इसमें हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है, बल्कि केवल अनुबंध का हवाला देकर नए संप्रभु द्वारा अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। रोक केवल अनुबंध में किसी भी बदलाव से संबंधित है, जबकि प्रतिवादी सही अर्थों में इसकी व्याख्या चाहता है, इसलिए अनुच्छेद 363 के तहत रोक वर्तमान मामले पर लागू नहीं है। एकमात्र विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत संपत्तियों की सूची के मद नंबर 14 के आलोक में सूट भूमि घरेलू विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में थी या नहीं। यदि कोई अधिकार दस्तावेज़ के माध्यम से बनाया गया है, तो प्रवर्तन की मांग हमेशा की जा सकती है।

19. यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्वव्यापी दृष्टि से मप्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 158(2) में किया गया संशोधन, अनुच्छेद 363 के तहत रोक अब कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि प्रतिवादी को "भूमिस्वामी" अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार नगरपालिका कानून का हिस्सा बन गए हैं, जिससे कानून की अदालत में उनके न्यायनिर्णयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस तथ्य के आलोक में कि महाराजा ने इन संपत्तियों के संबंध में भू-राजस्व का विधिवत भुगतान किया था और उनकी मृत्यु के बाद, प्रतिवादी-वादी ने इन संपत्तियों के लिए भू-राजस्व और अन्य शुल्क का भुगतान करना जारी रखा था, उन्हें शासक की निजी संपत्ति माना जा सकता है। रिकॉर्ड में यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध है कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(2) के अनुसार प्रतिवादी के पिता ने, देपालपुर जिला इंदौर के तहसीलदार का पत्र दिनांक 22 जुलाई 1963 (परिशिष्ट आर/9) के अनुसार इन विवादित भूमि में से एक मोहना बीर पर भूमिस्वामी का अधिकार हासिल कर लिया था। उक्त धारा उस शासक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करती है जो अनुबंध के आधार पर भूमि पर कब्जा कर रहा था या रखने का हकदार था। प्रतिवादी के पिता

वाद संपत्तियों के भूमिस्वामी होने के नाते प्रतिवादी को सिविल कोर्ट में वादभूमियो पर विवाद, यदि कोई हो, को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार देते हैं।

20. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि मध्य भारत राज्य के गठन के लिए मध्य भारत की विभिन्न रियासतों के विलय के परिणामस्वरूप अनुबंध उभरा था। प्रसंविदा के अनुच्छेद XII के संदर्भ में, तत्कालीन शासक द्वारा संपत्तियों की एक सूची प्रस्तुत की गई थी जिसे भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था और विवादित भूमि वास्तव में आइटम नंबर 14 के तहत कवर की गई है जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट है कि " सभी संपत्तियाँ होल्कर राज्य के घरेलू विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं"। यह तर्क देते हुए कि संपत्तियों की सूची में 'विविध' शीर्षक के तहत, संपत्तियों के विवरण का उल्लेख करने से पहले, यह विशेष रूप से नोट किया गया है कि "दावा की गई उपरोक्त संपत्तियों में निम्नलिखित में से मुख्य शामिल हैं:" इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सूची व्यापक नहीं है और "मुख्य में" शब्द यह प्रदान करते हैं कि केवल कुछ प्रमुख संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिससे अन्य संपत्तियों के लिए गुंजाइश बनती है जिनका उस सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। रिकॉर्ड से भी, यह स्पष्ट है कि विवादित संपत्तियों को होलकर राज्य के सेना विभाग ने वर्ष 1945 में "केवल एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में" एक वर्ष के लिए अपने कब्जे में ले लिया था, जिसका अर्थ है कि वास्तविक नियंत्रण हमेशा घरेलू विभाग शासक के पास रहा। मध्य भारत बल, ग्वालियर के मुख्यालय का दिनांक 22 जनवरी, 1951 का संचार (अनुलग्नक आर/3) भी इस संस्करण का समर्थन करता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि "एच.एच. इंदौर के घरेलू विभाग से किराए पर थी"। आर्मी ग्रास फार्म, इंदौर के अन्य संचार दिनांक 21 मई, 1951 और 30 मई, 1951 (अनुलग्नक आर/4 और आर/5) भी स्पष्ट रूप से इन संपत्तियों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-प्रभारी,

महाराजा की ओर से घरेलू विभाग को सौंपने का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा, तत्कालीन शासक की निजी संपत्तियों की सूची के खंड 20 में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि विलय के बाद मध्य भारत सरकार ऐसी संपत्तियों का कब्जा शासक को सौंप देगी जो सूची में निजी संपत्तियों के रूप में उल्लिखित हैं लेकिन मध्यभारत सरकार के नियंत्रण में हैं। तदनुसार, इन विवादित संपत्तियों का कब्ज़ा 30 मई, 1951 को शासक को दे दिया गया।

21. यह भी आग्रह किया जाता है कि यह अधिकार वैधानिक अधिकार के रूप में अनुबंध से स्वतंत्र भी मौजूद है। प्रतिवादी का दावा है कि इंदौर भूमि राजस्व और किरायेदारी अधिनियम, 1931 की धारा 31 के अनुसार, शासक का घरेलू विभाग एक साधारण किरायेदार बन गया और 26 अगस्त, 1926 के सरकारी आदेश के आधार पर, घरेलू विभाग को निपटान दरों पर भुगतान करना पड़ा। इसके बाद, मध्य भारत सरकार के राज प्रमुख के अधीन आने के बाद, घरेलू विभाग मध्यप्रदेश भूमि राजस्व और किरायेदारी अधिनिम 1950 की धारा 54(8) और धरा 54 (18) की दृष्टि में एक साधारण किरायेदार के रूप में बना रहा। इसके बाद, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190(1) सपठित धारा 185(1)(ii)(ए) के तहत सभी सामान्य किरायेदारों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये। राज्य द्वारा दिए गए इस तर्क का खंडन करते हुए कि ये संपत्तियाँ आरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में आती हैं और इसलिए, ऐसी भूमि पर कोई भूमिस्वामी अधिकार अर्जित नहीं हो सकता है, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त दावा पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है क्योंकि कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। राज्य को यह स्थापित करना होगा कि भूमि वन भूमि थी।

22. यह तर्क दिया जाता है कि विवादित भूमि पर वादी के अधिकार पहले से मौजूद अधिकार हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा संपत्तियों की सूची को मंजूरी देकर, अनुबंध और म.प्र. भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158 (2) के आलोक में मान्यता दी गई है इसलिए, ऐसे पहले से मौजूद अधिकारों के प्रवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 363 के प्रावधानों के तहत रोका नहीं जा सकता है क्योंकि जिस अधिकार को लागू करने की मांग की गई है वह केवल नगरपालिका कानून के तहत बनाया गया वैधानिक अधिकार है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी/वादी का अधिकार संप्रभु द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त पहले से मौजूद अधिकार है और यह संधि द्वारा नहीं बनाया गया था। माधवराव सिंधिया (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक कार्यकारी निकाय का आदेश अनधिकृत है या विधायी उपाय अधिकारातीत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत किसी भी अनुबंध से उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, वर्तमान विवाद को अनुबंध के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, वर्तमान विवाद को संविधान के अनुच्छेद 363 के दायरे में आने वाला नहीं माना जा सकता है और द्रौपदी देवी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्विवाद रूप से प्रसंविदा के अनुच्छेद XII के खंड 3 का परंतुक 1.7.1949 के बाद राज्य सहित किसी के भी द्वारा उठाये गये विवाद को प्रतिबंधित करता है।

23. दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, कानून के निम्नलिखित मुद्दे इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सामने आते हैं:

1. क्या वर्तमान मामले में विवाद को भारत सरकार के साथ शासक द्वारा दर्ज की गई संविदा की शर्तों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के प्रावधान आकर्षित होते हैं? यदि हां, तो क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत परिकल्पित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक सिविल मुकदमे में वादी/प्रतिवादी के अधिकारों का निर्णय करते समय वर्तमान मामले पर लागू होती है?

2. क्या मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(2) के तहत वादी को भूमिस्वामी का लाभ देने में न्यायालय सही था?

24. दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों और नीचे के न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर ध्यान देने से पहले, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 को निकालना उचित समझेंगे, जो इस प्रकार है:

363. कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक:

(1) इस संविधान में किसी भी बात के बावजूद, लेकिन अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के अधीन, किसी संधि, समझौते, अनुबंध, सगाई, सनद या अन्य समान के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। वह दस्तावेज़ जो किसी भारतीय राज्य के किसी भी शासक द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले दर्ज किया गया था या निष्पादित किया गया था और जिसमें सरकार एक पक्ष थी और जिसे जारी रखा गया है या ऐसे प्रारंभ के बादपरिचालन में जारी रखा गया है, या किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध, सगाई, सनद या अन्य समान साधन से संबंधित इस संविधान के किसी भी

प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या किसी दायित्व या दायित्व के संबंध में किसी भी विवाद में।

25. अनुच्छेद 363 के खंड (1) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह आभास होता है कि इस न्यायालय सहित इस देश में किसी भी न्यायालय के पास पूर्ववर्ती भारतीय राज्यो के शासक और भारत सरकार के बीच हुई संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

26. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, 16-06-1948 को प्रदर्श अनुबंध पी-79 के माध्यम से होल्कर के महाराजा अन्य रियासतों के साथ भारत के प्रभुत्व में विलय के लिए सहमत हुए।

27. प्रसंविदा के अनुच्छेद 12 के अनुसार, शासक अपनी निजी संपत्तियों पर अधिकारों का आनंद ले सकता है जो प्रसंविदा में शामिल हैं, जिसके लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों की एक सूची सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक था। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है:

(1) प्रत्येक संविदाकारी राज्य का शासक उस राज्य का प्रशासन राज प्रमुख को सौंपने की तिथि पर उससे संबंधित सभी निजी संपत्तियों (राज्य संपत्तियों से अलग) के पूर्ण स्वामित्व, उपयोग और आनंद का हकदार होगा।

(2) वह अगस्त 1948 के पहले दिन से पहले राज प्रमुख को निजी संपत्ति के रूप में उनके द्वारा रखी गई सभी अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों और नकद शेष की एक सूची प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि कोई विवाद उठता है कि क्या संपत्ति की कोई वस्तु शासक की निजी संपत्ति है या राज्य की संपत्ति है, तो इसे ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जाएगा जिसे

भारत सरकार राजप्रमुख के परामर्श से नामित कर सकती है और उसका निर्णय होगा व्यक्ति अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

...ऐसा कोई भी विवाद जुलाई 1949 के पहले दिन के बाद संदर्भित नहीं किया जाएगा।

28. अनुबंध के अनुच्छेद 12(2) के अनुसार, होल्कर के महाराजा ने विभिन्न शीर्षकों के तहत संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, विविध और खंड 14 में "होल्कर राज्य के घरेलू विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कुछ संपत्तियों को छोड़कर, उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति को छोड़कर, अचल संपत्तियों के रूप में प्रमुखों के तहत विवरण प्रस्तुत किया। घरेलू विभाग को पहले ही इंदौर के दो गेस्ट हाउसों में स्थानांतरित कर दिया गया था, अर्थात् एक इमारत में स्थित जिसे इंदौर छात्रावास के रूप में जाना जाता था और दूसरा बॉम्बे-आगरा रोड पर राजेंद्र भवन में स्थित था।

29. मुकदमे की अनुसूचित संपत्तियां जो वादी के कब्जे में हैं, संपत्तियों की पूरी सूची में उनका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वादी संपत्तियों की सूची के खंड 14 से संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त करता है जो घरेलू विभाग के नियंत्रण के तहत सभी संपत्तियों के बारे में बताता है। वादी अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए कि वाद अनुसूची संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं, संपत्तियों की सूची के खंड 14, इन संपत्तियों के संबंध में उसके और उसके पिता द्वारा भुगतान किए गए कर, संचार दिनांक 07-05-1948 और पत्र दिनांक 30-01-1956 पर निर्भर है जिसमें सूट अनुसूचित संपत्तियों को घरेलू विभाग को पुनः हस्तांतरित कर दिया गया। हालाँकि वादी की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए करों का भुगतान करने के बारे में बहुत सारे सबूत पेश किए गए थे कि मुकदमा अनुसूचित संपत्तियाँ शासक की निजी संपत्तियाँ हैं, मुख्य मुद्दा

जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या यह शासक की निजी संपत्ति है या संपत्ति राज्य की थी। संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई भी निष्कर्ष देने के लिए हमें हमेशा अनुबंध को देखना होगा क्योंकि अनुबंध वादी के लिए शीर्षक का स्रोत है। कल्पना के किसी भी स्तर पर, हम अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते कि वादी का अधिकार पहले से मौजूद अधिकार है। हर तरह से वादी का अधिकार अनुबंध से आता है जिसके आधार पर वादी इन संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा करता है, जो उसके अनुसार शासक की निजी संपत्ति घोषित की जाती हैं।

30. अनुच्छेद 363 का मात्र अवलोकन और मुकदमे में वादी द्वारा स्पष्ट शब्दों में मांगी गई राहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 में निहित प्रतिबंध को आकर्षित करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने द्रौपदी देवी के मामले में निर्णय को अलग करते हुए कहा कि यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। हमारी सुविचारित राय है कि उस मामले में निर्धारित कानून का नियम मौजूदा मामले पर लागू होता है। द्रौपदी देवी के मामले में इस न्यायालय ने कहा:

> 44.....संविदा राज्य के एक अधिनियम से उत्पन्न एक राजनीतिक दस्तावेज है। एक बार जब भारत सरकार शासक की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लेती है, उन संपत्तियों को छोड़कर जिन्हें वह निजी संपत्तियों के रूप में मान्यता देती है, तो किसी भी संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में मान्यता देने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी ओर, प्रसंविदा के इस खंड का अर्थ केवल यह है कि, यदि प्रसंविदा राज्य के शासक ने संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति होने का दावा किया है और भारत सरकार इससे सहमत नहीं है, तो यह शासक के लिए खुला था कि वह इस मुद्दे पर निर्णय खंड (3) द्वारा विचार किया

गया तरीका से ले। अनुच्छेद XII का खंड (3) का मतलब यह नहीं है कि सरकार इसे निजी संपत्ति के रूप में मान्यता देने में विफल रहने पर विवाद का उल्लेख करने के लिए बाध्य थी। दूसरे, यह विवाद कि क्या किसी विशेष संपत्ति को शासक की निजी संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी या नहीं, स्वयं अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न विवाद था। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 363 के कारण नगरपालिका अदालतों के अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण नगरपालिका अदालतों द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता।

31. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त अनुपात यह समझने में मदद करता है कि अनुबंध से पहले, सभी संपत्तियों का स्वामित्व शासक के पास निहित रहता है, लेकिन एक बार अनुबंध में प्रवेश होने के बाद, सरकार उन संपत्तियों को छोड़कर सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेती है। सरकार इसे शासक की निजी संपत्तियों के रूप में मान्यता देती है। इस अदालत ने स्पष्ट रूप से माना था कि किसी भी बाद के चरण में संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है, जब परिभाषित अवधि से पहले ही अनुच्छेद 12 के खंड (3) के संदर्भ में इस मुद्दे को उठाने का अवसर दिया गया हो। मौजूदा मामले में भी, इसी तरह का खंड मौजूद था, जहां किसी संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में मान्यता देने का विवाद केवल 1 जुलाई, 1949 से पहले उठाया जा सकता था। किसी संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी या नहीं, इस पर विवाद उत्पन्न होने वाला विवाद माना जाता था। अनुबंध की शर्तों का, जिससे संविधान के अनुच्छेद 363 के मद्देनजर न्यायालयों को इस पर निर्णय लेने से रोक दिया गया।

32. इसके अलावा माधव राव जीवाजी राव सिंधिया (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 363 की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी संधि के प्रवर्तन,

व्याख्या या उल्लंघन आदि से संबंधित विवाद को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से वर्जित किया गया है। रोक तभी लागू होती है जब विवाद किसी संधि, अनुबंध आदि के प्रावधानों से उत्पन्न हो रहा हो, जैसा कि वर्तमान मामले में है। इस न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 363 के दो भाग हैं। पहला भाग समझौतों और अनुबंधों आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है। इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार उस हिस्से के अंतर्गत आने वाले विवादों के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्जित है। इसके बाद अनुच्छेद 363 का दूसरा भाग आता है जो किसी भी समझौते, अनुबंध आदि से संबंधित संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या किसी दायित्व या दायित्व के संबंध में विवादों को संदर्भित करता है। इसमें विशेष रूप से उस अधिकार का उल्लेख किया गया था जैसा कि अनुच्छेद 363 में उल्लेख किया गया है, संपत्ति का प्रतीक है।

33. एक अन्य मामले में, करण सिंह (डॉ.) बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (2004) 5 एससीसी 698, एक संधि, अनुबंध आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए संविधान के अनुच्छेद 363 की प्रयोज्यता की जांच करते समय, यह न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों को किसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार का निर्धारण करने से रोक दिया गया है। शासक और सरकार के बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार अनुच्छेद 363 के अर्थ के अंतर्गत समझौते के बराबर होगा।

34. हमारी उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में तय किया है, प्रसंविदा राज्य का एक अधिनियम था और इसकी शर्तों से उत्पन्न कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में विषय वस्तु नहीं बन सकता है, और ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी बाद के चरण में निजी

संपत्ति के रूप में संपत्ति की कोई भी निहित मान्यता, जब परिभाषित अवधि से पहले ही अनुच्छेद 12 के खंड 3 के संदर्भ में मुद्दा उठाने का अवसर दिया गया हो; सबसे बढ़कर, संपत्तियों को अनुबंध में जगह नहीं मिलती है। वादी अनुबंध की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है कि सभी संपत्तियां जो घरेलू विभाग की हिरासत में हैं, शासक की निजी संपत्तियां हैं। हमारा मानना है कि इस तरह की व्याख्या और निहित मान्यता अस्वीकार्य है जैसा कि इस न्यायालय ने द्रौपदी देवी मामले में माना था। इसलिए निचली अदालत ने मामलों की श्रृंखला में इस अदालत द्वारा निर्धारित निर्णयों और कानून के प्रस्तावों पर ठीक से विचार किए बिना मुकदमे पर विचार करने में गलती की। इसलिए हमारा विचार है कि वाद में राहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के दायरे में आती है और वाद पोषणीय नहीं है। तदनुसार पहले मुद्दे का उत्तर अपीलकर्ता/राज्य के पक्ष में और प्रतिवादी/वादी के विरुद्ध दिया जाता है।

35. एक बार जब हम मुकदमे की रख-रखाव पर अपना निष्कर्ष दे देते हैं, तो हमें अन्य मुद्दों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वकील द्वारा दिए गए वैकल्पिक तर्क को देखते हुए, हमारा विचार है कि हमें उन मुद्दों पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वर्ष 1951 में भूमि होल्कर राज्य को पुनः हस्तांतरित कर दी गई थी, और पुनः हस्तांतरण बिना किसी अधिकार के है और यह बुरा है। विचारण न्यायालय ने माना कि यद्यपि यह वादी का विशिष्ट मामला है कि वे तौज़ी को भुगतान कर रहे हैं, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 1951 से पहले तौज़ी को भुगतान किया है और वादी और उसके पिता के पत्राचार से पता चलता है कि वाद अनुसूचित संपत्तियां संपत्तियों की सूची के आइटम नंबर 14 में शामिल नहीं किया गया था और आगे माना गया कि सूट अनुसूचित संपत्तियां वन विभाग को आवंटित की गई थीं। सबसे पहले वन विभाग को भूमि के हस्तांतरण के मुद्दे पर आते हैं, यह स्थापित कानून है कि पक्षकार अपनी दलीलों से शासित होती हैं

और इसका बोझ उस व्यक्ति पर होता है जो साबित करने की दलील देता है और इसके अलावा वादी को अपने मामले की ताकत के आधार पर सफल होना होता है और वह ऐसा नहीं कर सकता। प्रतिवादी के मामले की कमज़ोरी पर निर्भर करता है। कई आरोप लगाने के बाद भी राज्य यह दिखाने के लिए किसी भी दस्तावेज़ को चिह्नित करने में विफल रहा है कि संपत्तियों को वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और वर्ष 1951 में पुनर्हस्तांतरण बिना किसी कानूनी अधिकार के किया गया था। हालाँकि राज्य ने हमारे समक्ष कुछ दस्तावेज़ दाखिल किए हैं, लेकिन चूँकि वे साक्ष्य का हिस्सा नहीं हैं, हम उन दस्तावेज़ों को देखने के इच्छुक नहीं हैं।

36. मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में अपीलकर्ता राज्य ने दो दस्तावेजों को चिन्हित किया है। प्रतिवादी और वादी द्वारा की गई अपीलों को वापस लेते समय, अपीलीय अदालत ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि विचारण न्यायालय को किसी भी पक्ष को आगे सबूत पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। राज्य द्वारा अपीलीय न्यायालय के रिमांड आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया। रिमांड के बाद, मुकदमा विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि अदालत के सामने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि संपत्ति वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। यह निष्कर्ष अंतिम हो गया है क्योंकि अपीलकर्ता/राज्य द्वारा कोई क्रॉस अपील नहीं की गई है। इसलिए हम इन दस्तावेज़ों पर गौर करने के इच्छुक नहीं हैं।

37. वादी ने विशाल दस्तावेजी साक्ष्यों को चिह्नित करके और पीडब्लू 5 और पीडब्लू 7 की जांच करके स्थापित किया कि वे 1960 तक लगातार संपत्ति के कब्जे में थे, उस छोटी अवधि को छोड़कर जब सूट अनुसूचित संपत्ति सेना विभाग को दी गई थी। तौज़ी को महाराजा और बाद में वादी द्वारा भुगतान भी किया गया था। इस

संबंध में विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वादी यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है कि तौजी को 1951 से पहले भुगतान किया गया था, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत है। इन सभी कारकों के बावजूद कि महाराजा और वादी के पास लगातार संपत्ति का कब्ज़ा था और उन्होंने संपत्तियों के लिए तौज़ी को भुगतान किया था, चाहे वादी का कब्ज़ा कितने भी लंबे समय तक क्यों न हो और करों का भुगतान करने से उसे इन संपत्तियों के स्वामित्व की घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा जब एक प्रसंविदा का हिस्सा हैं और प्रसंविदा की व्याख्या की मांग करते हैं। इसके अलावा, वादी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासकीय सामान्य, प्रशासनिक विभाग, भोपाल को दिनांक 1 अक्टूबर 1962 को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने वाद की अनुसूचित संपत्तियों को महाराजा होल्कर द्वारा घोषित निजी संपत्तियों के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कार्रवाई का पूरा कारण और मुकदमे में मांगी गई राहतें अनुबंध और अनुबंध से प्राप्त अधिकारों पर आधारित हैं।

38. हम इस चर्चा में जाने के इच्छुक नहीं हैं कि भूमि का पुनः हस्तांतरण बिना अधिकार के है या नहीं, क्या ये संपत्तियाँ घरेलू विभाग के नियंत्रण में हैं क्योंकि यह अनुबंध में से उत्पन्न होने वाले विवाद का निर्णय करने के समान है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत वर्जित है। यहां तक कि एक मिनट के लिए यह मान भी लिया जाए कि ये संपत्तियां घरेलू विभाग के नियंत्रण में हैं, फिर भी वादी सफल नहीं हो सकता क्योंकि होलकर के महाराजा ने संपत्तियों की सूची में इन संपत्तियों का विशेष रूप से उल्लेख करने में विफल रहे हैं, और अनुबंध की व्याख्या स्थापित कानून के अनुसार अनुमत नहीं है।

39. दूसरा निष्कर्ष जिसे हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वह यह है कि महाराजा संपत्ति के मालिक होने के साथ-साथ किरायेदार भी हैं। वादी द्वारा मांगे गए सभी

अधिकार केवल प्रसंविदा से प्राप्त अधिकार हैं। जैसा कि अनुबंध के खंड 12(1) के तहत प्रदान किया गया है, दिनांक 29-9-1962 के पत्र द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी/वादी ने अनुबंध के माध्यम से शीर्षक का दावा किया है, न कि ऐसे किसी किरायेदारी अधिकार के द्वारा। इसलिए, प्रतिवादी वादी वाद अनुसूची संपत्तियों पर किरायेदारी के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है और ऐसी याचिका गलत है और उसे ऐसी याचिका उठाने से रोका गया है।

40. अब हम दूसरे मुद्दे यानी मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(2) की प्रयोज्यता से निपटना चाहेंगे। उक्त धारा 2 अक्टूबर, 1959 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुई और इस प्रकार पढ़ी गई:

> 158(2): मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बनने वाले एक भारतीय राज्य का एक शासक, जो इस संहिता के लागू होने के समय भूमि धारण कर रहा था या अनुबंध या समझौते के आधार पर ऐसे शासक के रूप में भूमि धारण करने का हकदार था। संविधान के प्रारंभ से पहले उनके द्वारा दर्ज किया गया, इस संहिता के लागू होने की तारीख से, संहिता के तहत ऐसी भूमि का भूमिस्वामी होगा और भूमिस्वामी को प्रदत्त और लगाए गए सभी अधिकारों और देनदारियों के अधीन होगा या इस संहिता के अंतर्गत।

धारा 158(2) के अनुसार भूमिस्वामी के अधिकार प्रदान करने हेतु, शासक के पास भूमि होनी चाहिए या उसके द्वारा किए गए अनुबंध या समझौते के आधार पर उसे ऐसे शासक के रूप में भूमि रखने का हकदार होना चाहिए। वादी/प्रतिवादी प्रसंविदा से स्वतंत्र भूमिस्वामी का दर्जा नहीं मांग सकता क्योंकि धारा 158(2) के तहत अधिकार प्रसंविदा से ही उत्पन्न होते हैं। भूमि को धारण करने का स्रोत एक अनुबंध के आधार पर उत्पन्न होता है। जब अनुबंध के माध्यम से दावा किया गया अधिकार विवादित है

और इन विवादों को निपटाने की राहत संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत वर्जित है, तो हमारे विचार में, कोई भी अनुबंध से स्वतंत्र, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 158(2) के तहत "भूमिस्वामी" होने का दावा नहीं कर सकता है। तदनुसार, यह मुद्दा अपीलकर्ता/राज्य के पक्ष में और प्रतिवादी/वादी के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि वादी द्वारा घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत वर्जित है और वादी मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 158 (2) के तहत भूमिस्वामी पर अपना अधिकार बताते हुये किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

41. उपरोक्त सभी कारणों से, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करके इन अपीलों की स्वीकार करते है और परिणामस्वरूप वाद खारिज किया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।